

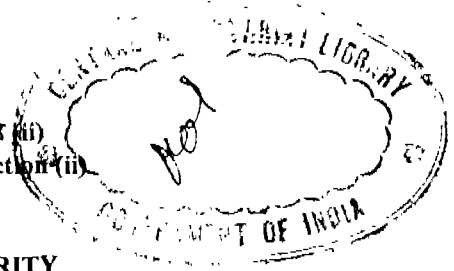


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 692]
No. 692]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 13, 1995/अग्रहायण 22, 1917
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 13, 1995/ AGRAHAYANA 22, 1917

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1995

का० आ० 970(अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) (दो सौ इकत्तीसवां संशोधन) नियम, 1995 है।
(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।
2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,—
(क) "विदेश मंत्रालय" शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 43 और उसके नीचे टिप्पण के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—
"44. मानव अधिकार :
(i) विदेश में मानव अधिकार संगठनों से पारम्परिक प्रभाव;
(ii) अंतरराष्ट्रीय घोषणाएं, संधियां, अभिसमय और सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र और उसके अन्य विशिष्ट अधिकरणों और संगठनों से प्राप्त निर्देश;
(iii) संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय अभिसमय जिनका भारत एक पक्षकार राज्य है, के अधीन अपेक्षित रिपोर्टिंग दायित्वों का, संबद्ध मंत्रालयों के समन्वय से कार्यान्वयन।

टिप्पण :—इन कृत्यों का प्रयोग विदेश मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय के निकट समन्वय से किया जाएगा, जो कि नीति और मानवाधिकारों से संबंधित सभी मामलों के समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय होगा।";

(ख) "गृह मंत्रालय" शीर्षक के नीचे "ख. राज्य विभाग" उप-शीर्षक के नीचे प्रविष्टि 14 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"14. मानव अधिकार :—

- (i) "मानव अधिकार" के मामलों के संबंध में साधारण नीतियों के लिए नोडल अधिकरण के रूप में, जिनके अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या इस संबंध में कोई अन्य संस्थागत व्यवस्था भी है, कार्य करना;
- (ii) पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों द्वारा की गई अभिकथित ज्यादतियों से संबंधित मानव अधिकारों के अतिक्रमण;

- (iii) देश के भीतर मानव अधिकार संगठनों और अन्य संबंधित संगठनों से पारस्परिक प्रभाव और विभिन्न विभागों और राज्य सरकारों से समन्वय;
- (iv) मानव अधिकारों के संबंध में नीति का समन्वय।

टिप्पण :—गृह मंत्रालय मानव अधिकारों से संबंधित समग्र नीति के लिए नोडल मंत्रालय होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य, महिलाएं, अल्पसंख्यक, बच्चे और बंधुआ मजदूर जैसे विशिष्ट समूहों के कल्याण और सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए मुख्य रूप से संबंधित विभाग इन विशिष्ट समूहों के मानव अधिकारों को सुरक्षित रखने के संबंध में उत्तरदायी होंगे।''।

[फा० सं० 74/2/2/95-मंत्रि]

शंकर दयाल शर्मा

राष्ट्रपति

एस० के० मिश्रा, संयुक्त सचिव

**CABINET SECRETARIAT
NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th December, 1995

S.O. 970 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two Hundred and Thirty-First Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(a) under the heading "MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (VIDESH MANTRALAYA)", after entry 43 and the note thereunder, the following entry shall be added, namely :—

"44. Human Rights :

- (i) Interaction with Human Rights Organisations abroad;
- (ii) International declarations, treaties, conventions and conferences; references received from the United Nations and other specialised agencies and organisations thereof;
- (iii) Implementation of reporting obligations, in coordination with the concerned Ministries, required under the United Nations and international conventions, to which India is a State party.

NOTE.—These functions will be exercised by the Ministry of External Affairs in close co-ordination with the Ministry of Home Affairs, which shall be the nodal Ministry for policy and for co-ordination of all matters relating to Human Rights."

(b) under the heading "MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)", under sub-heading "B. DEPARTMENT OF STATES (RAJYA VIBHAG)", for entry 14, the following entry shall be substituted, namely :—

"14. Human Rights :—

- (i) To act as the nodal agency for the general policies regarding "Human Rights" matters including National Human Rights Commission or any other institutional arrangements in this regard;
- (ii) Human rights violations relating to alleged excesses by personnel of police and paramilitary forces;
- (iii) Interaction with Human Rights organisations and other related organisations within the country and coordination with various departments and State Governments;
- (iv) Coordination of policy relating to Human Rights.

NOTE.—Ministry of Home Affairs will be the nodal Ministry for overall policy relating to Human Rights. The departments primarily concerned with the welfare and socio-economic development of specific groups like members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, women, minorities, children and bonded labour, shall be responsible in respect of preservation of Human Rights of the specified groups."

[F. No. 74/2/2/95 Cab.]

SHANKER DAYAL SHARMA
PRESIDENT

S.K. MISRA, Jt. Secy.